अच्छे दिन आयेंगे, लेकिन कब ??

सुविधाएँ तो ख़राब ही होती है

निजी में दो पैसे ज्यादा देने पड़ते है, पर गुणवत्ता तो मिलती है

सरकार के पास सभी सुविधाओं के लिए पैसे नहीं हैं..

हमे सिर्फ सरकार को दोष देना आता है ....

हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी है की नहीं सरकार के प्रति?

ये सभी बातें हमारे रोजमर्रा के जीवन की हैं। हाय रे सरकार ... बेचारी सरकार! हमें अच्छी सुविधाएँ देने के लिये सरकार के पास पैसे नही हैं? सरकार वास्तव में गरीब है क्या?

इस देश की सरकार गरीब नहीं है!

हमारी सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन सरकार गरीबों पर खर्च करने के बजाय अलग - अलग (कानूनी/गैरकानूनी) तरीकों से अमीरों के जेब और तिजोरियाँ भर रही हैं।

सन २००५ से सरकार ने अब तक अमीरों को ५३ लाख करोड़ की करमाफी (टैक्स माफ़ी) दी है। सिर्फ पिछले वर्ष २०१६-१७ साल में अमीरों को ५.५ लाख करोड़ रु. का कर माफ किया हैं। वहीं दूसरी तरफ इस साल गरीबों पर सिर्फ १.९४ लाख करोड़ रू. का खर्च ही प्रस्तावित किया हैं।

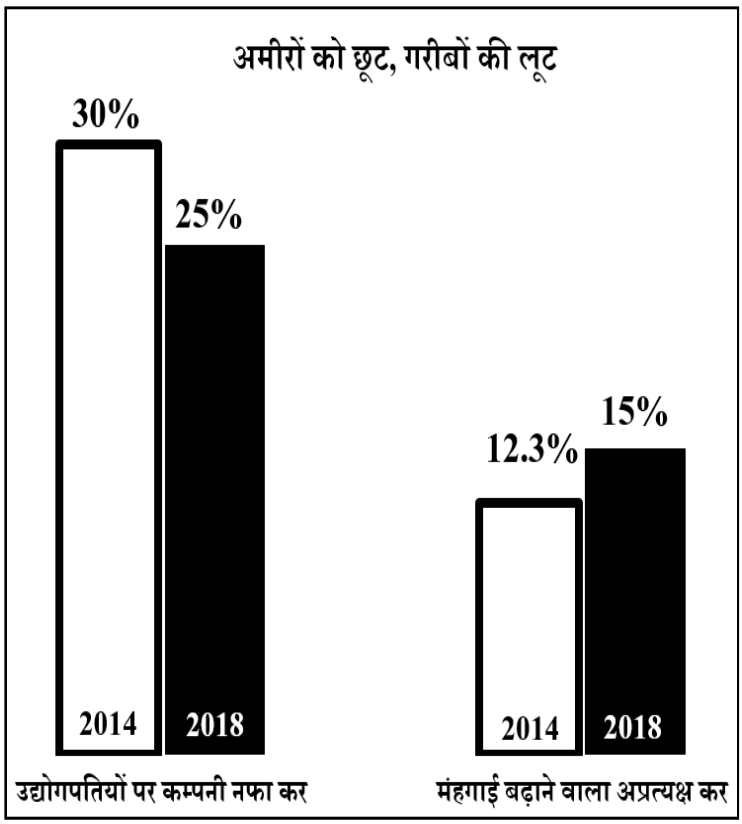

उद्योगपतियों और पैसेवालों पर और मेहरबानियां

- निजी-सरकारी भागीदारी के नाम से कम्पनियों को हजारों करोड़ो का अनुदान|
- सरकारी बैंकों के लाखो करोड़ों के कर्ज डुबाने वाली व माल्या जैसे अनेक उद्योगपतियों पर किसी भी प्रकार की कोई भी कारवाई नही|
- कौड़ी के भाव में कम्पनियों को प्राकृतिक साधन-सम्पत्ती का हस्तांतरण|
- सरकारी विद्यालयों, दवाखानों, बिजली इनका बाजारीकरण|
- अमीरों पर टैक्स कम किये जा रहे और वही गरीब जनता को लुटने वाले टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं|

इससे यह समझ में आता है कि सरकार और बड़ी-बड़ी कम्पनियों की मिली-भगत हैं। इनको आम

जनता से कोई लेना देना नही हैं। इसिलये देश के मुख्य आर्थिक सलाहगार, अरविंद सुब्रमण्यम बोलते है कि, "पूंजीपतियों ने कितना ही कर्ज डुबाया हो, तब भी उन्हें कर्जमाफी देनी चाहिये। यह पूंजीवादी व्यवस्था का तरीका हैं।

दूसरे देशों कि हालत देखी जाए ...

हमें अचंभा होगा लेकिन दुनिया में युरोप, अमेरिका जैसे विकसित और ब्राजील, मेक्सिको, क्युबा और अफ्रिका के भी विकासशील देशों में लोगों के सामाजिक सुरक्षा हेतु बहुत सारी योजनायें अस्तित्व में हैं। बेरोजगारी भत्ता, सभी के लिये स्वास्थ्य सुविधायें, मुफ्त विद्यालयीन शिक्षा, मुफ्त या सस्ती उच्च शिक्षा, बुढ़ापे में पेंशन, मातृत्व अनुदान, किसी भी प्रकार की आय से वंचितों को गरिबी भत्ता और इस तरह की अनेक सुविधाएं लोगों को लगातार मिले इसलिये यह सारे देश बड़े पैमाने पर निधी खर्च करते हैं। जबकि इन देशो की तुलना में भारत का सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च बहुत ही कम हैं।

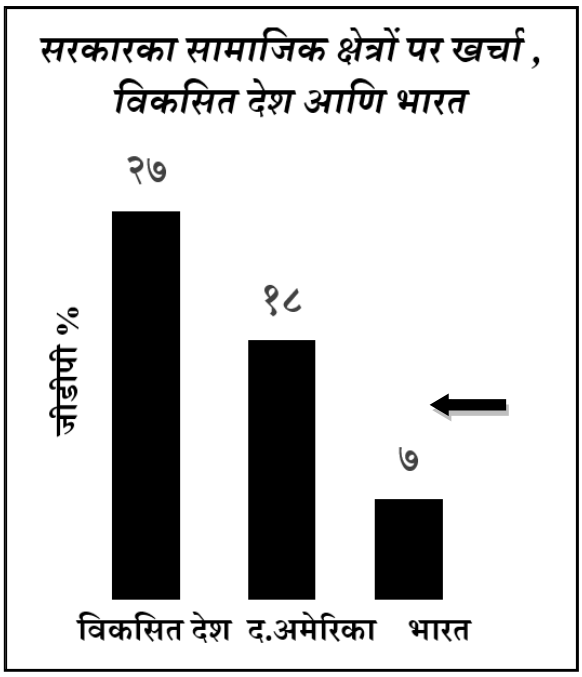

यदि अमीरों पर ५.५ लाख करोड़ रू करमाफी नही कि होती तो... ?

- भारत के सभी बच्चों को बाराहवी तक की मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती
- सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो जाती
- सभी बुजुर्गों को पेंशन मिल जाती
- युवाओं को सरकारी नौकरियाँ मिल जाती
- राशन पर आवश्यक अनाज अच्छे दर्जे का और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते

सोचिये... पिछले १३ सालों में अमीरों को दी गयी ५३ लाख करोड़ रू. की कर माफी के बजाय क्या - क्या हो सकता हैं? फिर तो वाकई में भारत के सामान्य-गरीब लोगों के वाकई में अच्छे दिन आ गये होते। लेकिन...

गंगाधर ही शक्तीमान है

जी हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है! काँग्रेस से परेशान होकर लोगों ने नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को चुना। यह सरकार भी काँग्रेस की सभी जनविरोधी नीतियां वैसी की वैसी ही लागू कर रही हैं। कांग्रेस दवारा बनाई ख़राब नीतियों से बदत्तर नीतियां भाजपा सरकार शायद और अधिक तेजी से लागू कर रही हैं। यह सब देखते हुए लगता है कि काँग्रेस और भाजपा ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं, सिद्ध होता हैं। 'सबका साथ, सबका विकास' ऐसा सिर्फ नारा देते हैं, बल्कि' अमीरों का साथ, अमीरों का विकास' को ही दोनों ही लागू कर रहे हैं।

सच्चे "अच्छे दिन" आयेंगे... कब?

सच्चे अच्छे दिन तभी आयेंगे जब हम काँग्रेस और भाजपा इन दोनों पक्षों से किसी भी प्रकार की उम्मीद-अपेक्षा रखना बंद कर देंगे। हमें इनके असली रूप से वाकिफ होना चाहिये कि दोनों ही'सूट बूट की सरकार' चलाते हैं। सच्चे अच्छे दिन तभी आयेंगे जब हम अपने हक और अधिकार समझ जायेंगे, दुसरों को भी बतायेंगे और ये प्राप्त करने के लिये एक साथ संघर्ष करेंगे। हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं।